उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सूभाष रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 08 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–04(07/54)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत रविवार को देहरादून के एक स्थानीय वैडिंग प्वाइंट में पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत द्वारा आयोजित मैंगो, पहाड़ी ककड़ी, भुट्टा पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड की संस्कृति व यहां के स्वादिष्ट पौष्टिक उत्पादों का संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 08 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–03(07/53)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को मसूरी स्थित एक होटल में एसोसिएशन ऑफ देवभूमि फार्मा इंडस्ट्रीज उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित इंडस्ट्री इंट्रेक्शन प्रोग्राम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और उद्योगों के बीच कोर्डिनेशन के लिए प्रमुख सचिव उद्योग की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जायेगी, जिसमें सचिव स्वास्थ्य, सचिव ऊर्जा, एमडी सिडकुल, दो प्रतिनिधि कॉसमेटिक इंडस्ट्री एवं सीआईआई के उत्तराखण्ड के अध्यक्ष इस कमेटी में सदस्य के रूप में रहेंगे। बायोडायवर्सिटी बोर्ड एवं प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी भी आवश्यकता पड़ने पर बैठक में प्रतिभाग करेंगे। आयुर्वेद एवं फार्मा के लाइसेंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जायेगा। सेलाकुई क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति के लिए 230 केवी के सब स्टेशन की स्थापना की जायेगी। सेलाकुई पुलिस चौकी को उच्चीकृत कर थाने में बदला जायेगा और इसमें महिला पुलिस की संख्या बढ़ाई जायेगी। उद्योगों के सहयोग से एक औषधी कोष (मेडिकल बैंक) बनाया जायेगा। औषधी एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत किये जाने वाले गुड्स मैनीफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जीएमपी) की वैधता एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष की जायेगी साथ ही मार्केट स्टेंडिंग सेर्टिफिकेट (एम.एस.सी) की वैधता भी एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष की जायेगी। भगवानपुर क्षेत्र में उद्योगों हेतु सेंट्रल ईटीपी प्लांट लगाया जायेगा। औषधी विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए नवीन ढ़ाचा जल्द ही केबिनेट में प्रस्तुत किया जायेगा। आयुर्वेदिक औषधी निर्माण एवं नियंत्रण विभाग के अधिकारी, केन्दीय औषधी मानक संगठन के अधिकारियों से समन्वय बनाकर विभाग से संबंधित समस्याओं का निदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टरों को हर सम्भव सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा। जिससे अधिक से अधिक उद्योग उत्तराखण्ड में निवेश कर सकेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर युवाओं एवं महिलाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाने एवं राजस्व में वृद्धि के लिए उद्योगों के पदाधिकारियों से समय–समय पर बैठक करना जरूरी है। ऑल वेदर रोड एवं भारत माला योजना, रेलवे एवं हवाई सेवाओं में वृद्धि होने से आगामी दो सालों में प्रदेश में आवागमन के साधन और सुगम होने के बाद उद्योगों का उत्त्राखण्ड में रूझान और अधिक बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पलायन को रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे–छोटे उद्योगों को विकसित कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की शीघ्र प्राथमिकता है। 04 एवं 05 अक्टूबर को देहरादून में इनवेस्टर मीट किया जायेगा, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने सभी उद्योगों के पदाधिकारियों से अपील की कि इस इनवेस्टर मीट में अपने इनोवेटिव सुझाव दें।

वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत ने कहा कि राज्य गठन के बाद उत्तराखण्ड में छोटे–बड़े उद्योगों में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्तमान में प्रदेश में 41 हजार लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग हैं। 300 बड़ी इंडस्ट्रियां हैं। औषधी के क्षेत्र में देश का 20 प्रतिशत प्रोडक्ट उत्तराखण्ड में बन रहा है। एमएसएमई के तहत सरकार विशेष इन्सेंटिव दे रही है। जीएसटी में सभी 17 प्रकार के टेक्स को समायोजित कर देशभर में एक ही कर प्रणाली की व्यवस्था की गई है। जीएटी काउंसिल ने अनेक सुधारात्मक कदम उठाये हैं।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉ. एस. ऐश्वर्य रेड्डी, सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश झा, सचिव वित्त श्री अमित नेगी, सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा, एमडी सिडकुल श्रीमती सौजन्या, चैयरमेन एसोसिएशन ऑफ देवभूमि फार्मा इंडस्ट्रीज श्री संदीप जैन, उत्तराखण्ड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता एवं विभिन्न उद्योगों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 08 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–02(07/52)**

मा.उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य किया जा रहा है।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि इस अभियान के अन्तर्गत रविवार को 20 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 143 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 815 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, 2569 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व 75 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि शहर में अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य पूरी निगरानी व नियमानुसार अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ अवैध भवनों के भवन स्वामियों द्वारा स्वयं भी ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग भविष्य में दुबारा अतिक्रमण करते है, ऐसे लोगों के विरूद्ध आई.पी.सी. की धाराओं के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण में आम जन मानस का सहयोग निरन्तर शासन–प्रशासन को मिल रहा है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 08 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–01(07/51)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को ऋषिपर्णा नदी के उद्गम स्थल मासी फॉल का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से मिशन रिस्पना से ऋषिपर्णा के लिए जनसहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को रिस्पना के उद्गम से मोथरोवाला तक एक ही दिन में 2.5 लाख से अधिक अनेक प्रजाति के पौधे लगाये जायेंगे। जिसमें फलदार वृक्ष, चारा प्रजाति के एवं जल संरक्षण करने वाले पौधे लगाये जायेंगे।

22 जुलाई को होने वाले पौधरोपण, सामाजिक संगठनों, संस्थाओं व जन सहयोग से किये जायेंगे। कोसी नदी पर 1. 5 लाख से अधिक पौधे लगाये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारम्भिक चरण में रिस्पना एवं कोसी नदी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद अन्य नदियों को भी पुनर्जीवित किया जायेगा। आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए जल संरक्षण की दिशा में विशेष प्रयासों की जरूरत है। इसके लिए सरकारी संस्थानों में रेन वाटर हॉर्वेस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि जो लोग 22 जुलाई को रिस्पना नदी पर वृक्षारोपण नहीं कर पायेंगे व लोग ''मेरा वृक्ष मेरी याद'' के भाव से अपने घरों या उसके आसपास एक वृक्ष अवश्य लगाएं। जल संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करना जरूरी है। हमें जो जल स्रोत सूख गये हैं, उन्हें पुनर्जीवित करना होगा। देहरादून को पूर्ण ग्रेविटी का पानी उपलब्ध कराने के लिए मार्च 2020 तक सौंग बांध बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जून 2019 तक सूर्यधार जल विद्युत परियोजना को पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा।

इस अवसर पर जिलाधिकारी देहरादून श्री एस.ए.मुरूगेशन, वी.सी.एमडीडीए श्री आशीष श्रीवास्तव एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।